Indu Kumari.

Assistant. Professor, Dept. of Economics, B. N. College, Bhagalpur,
T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur,

Study material of B.A Part-2 (paper-3),Module-7

मौद्रिक नीति

यह नीति सरकार तथा केंद्र बैंक की उस नियंत्रण नीति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्राउसकी लागत तथा ब्याज दर तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने को उपाय किए जाते हैं।

संकुचित अर्थों में मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति से है। विस्तृत अर्थों में मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत आदि को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपाय के अतिरिक्त ऐसी अमौद्रिक नीतियां और उपाय भी सम्मिलित किए जाते हैंजिसका प्रभाव देश की मौद्रिक स्थिति पर पड़ता है ।

पॉल इंजिन के अनुसारमौद्रिक नीति में "वे सब मौद्रिक निर्णय तथा उपाय जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली पर प्रभाव डाला होता है सम्मलित होते हैं।"

जॉनसन ने इस नीति को इस प्रकार परिभाषित किए हैं "सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के औजार के रूप में यह नीति है।"

जी.के .शा इसे इस प्रकार परिभाषित की" मुद्रा की मात्राप्राप्यता या लागत को परिवर्तित करने के लिए मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा कोई सचेत कारी किया गया।"

मौद्रिक नीति अपना कार्य मुख्यता मुद्रा मात्रा में परिवर्तन द्वारा करती है। इससे मुद्रा के रुप में व्यक्त की जाने वाली उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकते हैं।

मौद्रिक नीति के उद्देश्यों

1)पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार को मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य में रखा गया है । यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि बेरोजगारी से ना केवल संभावित उत्पादन की हानि होती है बल्कि इससे सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की भी हानि होती है। । इसके अतिरिक्त यह गरीबी को उत्पन्न करती है इसलिएए पूर्ण रोजगार प्राप्त करना परम आवश्यक होता है।

2)कीमत स्थिरता - कीमत स्तर में स्थिरता लाना मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है।

3) आर्थिक वृद्धि- हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों मे से एक उद्देश्य यह रहा है कि अर्थव्यवस्था की तेजी से आर्थिक समृद्धि हो।

4)भुगतान शेष- 1950 के दशक से मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य रहा है कि भुगतान शेष संतुलन बनाए रखा जाए।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीति के उद्देश्य से भिन्न नहीं होते हैं । समय में परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं, परिणामस्वरुप आर्थिक नीति के उद्देश्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग-अलग रहते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों पर अर्थव्यवस्था के स्वरूपआर्थिक संगठन तथा विकास के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय बैंक अथवा मौद्रिक अधिकारी को यह निर्णय करना पड़ता है कि मौद्रिक नीति का उपयोग करते समय किन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाए इस प्रकार की निर्धारित प्राथमिकताए देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित होती है और समय-समय पर इनमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि एक ही समय पर अलग-अलग देशों में मौद्रिक नीति का प्रयोग अलग-अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता सकता है।

मौद्रिक नीति के उपाय/ उपकरण

केंद्रीय बैंक के द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपना गए उपायो को मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं । साख की मात्रा अधिक होने पर कुल माँग का स्तर बढ़ता है क्योंकि लोगों के पास वव्य करने के लिए अधिक अधिक धनराशि होती है। इसकी विपरीत साख की मात्रा के कम होने पर मांग कम होती है। मौद्रिक नीति के उपकरण को दो भागों में

बांटा जाता है पहला मात्रात्मक इसे अप्रत्यक्ष नियंत्रण नीति भी कहते हैं दूसरा गुणात्मक अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति कहते हैं।

साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय पाए जाते हैं ।मात्रात्मक उपकरणो के माध्यम से ब्याज की दर अथवा साख की लागत को प्रभावित किया जाता है , परिणामस्वरूप साख में संकुचन अथवा विस्तार होता है। चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि द्वारा व्यापारिक बैंको की साख देने की क्षमता प्रभावित होती है।

इन उपकरणों के द्वारा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख के संपूर्ण स्तर का नियमन करना है।

मौद्रिक नीति के उपकरण की व्याख्या निम्न प्रकार से हैं

· बैंक दर नीति- बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है। जब केंद्रीय बैंक देता है की अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही होती है तब बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक से उधार लेना महंगा होता है परिणाम स्वरुप व्यापारिक बैंक भी अपने ग्राहकों को ऊंची ब्याज दर पर उधार देती है।

इस कारण उधार लेने वालों की संख्या में कमी आती है तथा साथ संकुचन होता है और कीमतें तथा वस्तु कि मांग मैं कमी आती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है ए तब केंद्रीय बैंक बैंक दर को कम करती है क्योंकि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहती है। बैंक दर के कम होने के परिणाम स्वरुप व्यापारिक बैंक भी अपना ब्याज दर को घटा देती है जिसके फलस्वरुप ग्राहकों को उधार लेने में सुविधा होती है तथा वस्तुओं के मांग में वृद्धि होती है फलस्वरुप अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय तथा मांग बढ़ना शुरू हो जाता है।

· खुले बाजार के प्रचालन-

खुले बाजार के प्रचालन मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतिओ के क्रय विक्रय से संबंध रखते हैं जब कीमतें बढ़ने लगती है और उन्हें रोकने की जरुरत होती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचती हैं। व्यवसायिक बैंकों के रिजर्व घट जाते हैं और वे अधिक उधार देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं ए फलस्वरुप निवेश हतोत्साहित होता है और कीमतों में वृद्धि रुक जाती है इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी के स्थिति होती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूति

को खरीदता है जिससे व्यापारिक बैंक के आरक्षण बढ़ जाते है और ऐसे बैंक ज्यादा से ज्यादा साख का निर्माण कर सके जिसके परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि हो ।उत्पादन, रोंजगार तथा मागँ और कीमतों का गिरना रुक जाए।

· आरक्षित जमा कोश में परिवर्तन-

प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा किए निशित न्यूनतम राशि आरक्षित कोश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है। यह आरक्षित कोश जितना अधिक होता है एव्यापारिक बैंक के पास नगदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम होता है इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख का निर्माण होता है।

· चयनात्मक साख का नियंत्रण

. विशिष्ट उद्देश्य से विशेष प्रकार की साख को प्रभावित करने के लिए चयनात्मा या गुणात्मक साख नियंत्रण काम में ले जाते हैं। अर्थव्यवस्था के भीतर सट्टा क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए व सामान्यता परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताओं का रुप ले लेते हैं ।जब अर्थव्यवस्था में अथवा विशेष शेत्र में कुछ वस्तु में ज्यादा सट्टा क्रिया होती है और कीमतें पढ़ना शुरू हो जाती है , तो केंद्रीय बैंक उन पर सीमा आवश्यकता बढ़ा देता है। परिणाम यह होता है कि उधार लेने वालों को विशिष्ट प्रतिभूतियाँ पर ऋण के रूप में कम मुद्रा दी जाती है ।विशिष्ट क्षेत्रों में मंदी की स्थिति में केंद्रीय बैंक आवश्यकताएं सीमा घटाकर उधारग्रहण को प्रोत्साहन देता है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका-

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति साख की लागत तथा प्राप्यता को प्रभावित करकेए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके तथा भुगतान शेष संतुलन को कायम रहकर आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम करती है। अतः ऐसे देशों में मोद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए साख नियंत्रण करना, विनिमय दर को स्थिर करना , भुगतान शेष में संतुलन प्राप्त करीना तथा आर्थिक विकास बढ़ाना है।

1) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना

विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीति के दबाव पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को साख नियंत्रण के मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के उपायों की आवश्यकता होती है।

विकासशील देशों में साख नियंत्रण करने के लिए बैंक दर की नीति तथा खुले बाजार की प्रक्रिया की तुलना में परिवर्तनशील रिज़र्व अनुपात ज्यादा प्रभावशाली होता है।

साख के आवंटन को प्रभावित करने और निवेश की पद्धति को प्रभावित करने में मात्रात्मक उपाय की अपेक्षा गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय ज्यादा प्रभावशाली होते हैं।

2) कीमत स्थिरता प्राप्त करना-

विकासशील अर्थव्यवस्था मे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक क्षेत्रों में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग बढ़ती है। इससे लेनदेन तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ती है इसलिए मौद्रिक अधिकारी को मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तथा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा की पूर्ति को तथा मुद्रा की मांग के अनुपात से अधिक बढ़ाना पड़ता है।

3) भुगतान शेष घाटा कम करना-

ब्याज दर नीति के रूप में मौद्रिक नीति भुगतान शेष के घाट को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। विकास के नियोजित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्था को गंभीर भुगतान शेष की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मौद्रिक नीति कि ऊंची ब्याज दर द्वारा भुगतान शेष के घाट को कम करने में सहायक हो सकती है । ऊंची ब्याज दर निवेश के अंतर प्रवाह को प्रोत्साहन देकर भुगतान शेष के अंतर को कम करने में सहायक होती है।

4) ब्याज दर नीति-

विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ऊंची ब्याज दर नीति अधिक बचत को प्रोत्साहित करती हैए बैंकिंग आदतें विकसित करती है ए तथा अर्थव्यवस्था मुदीकरण को तीव्रता प्रधान करती है ए जो पूंजी निर्माण और आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंची ब्याज दर नीति स्थिति को

दूर करने वाली भी है क्योंकि यह सट्टे तथा करेंसियो के लिए उद्धार लेने और निवेश करने को हतोत्साहित करती ह। इस नीति के अनुसार अनावश्यक तथा अनुउत्पाद प्रयोग के लिए ऊंची ब्याज दरें और उत्पादकीए प्रयोगो के लिए नीची ब्याज दरें होनी चाहिए।

5) बैंकिंग और वित्तीय संस्था स्थापित करना

विकासशील देशों में मौद्रिक नीतिका एक उद्देश्य पूंजी निर्माण के लिए बचतों को जुटाना ए प्रवाहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के स्थापना तथा विकास करना होता है।

6)ऋण प्रबंधन

एक विकासशील देश में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसका लक्ष्य है सरकारी बंडों का उचित समय पर जारी करना, उन की कीमतों को स्थिर करना, और सार्वजनिक ऋण की सेवा लागत को न्यूनतम बनाना।

इस प्रकार समुचित मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने भ्रुगतान शेष इस अंतराल हो कम करके, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करनेतथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है।

विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएं

विकासशील देशों का अनुभव यह बताता है कि मौद्रिक नीति कि ऐसे देशों में सीमित भूमिका होती है जो निम्न प्रकार से है

1) विशाल गैर मुद्रिका क्षेत्र कहां हो ना ऐसे देशों के लिए चुनौती होती है।ए

2) अविकसित मुद्रा और पूंजी बाजार का होना ऐसे देशों में मौद्रिक नीति को सीमित करता है।

3) बहुसंख्यक गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ का होना मौद्रिक नीति की सफलता को सीमित करती है।

4) व्यवसायिक बैंकों के पास अधिक तरलता पाई जाती है , जिससे वे केंद्रीय बैंक की साख नीति द्वारा प्रभावित नहीं होते परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति कम प्रभावशाली हो जाता है।

5) ऐसे देशों में मौद्रिक नीति इसलिए भी सफल नहीं होती है ए क्योंकि बैंक मुद्रा देश में कुल मुद्रा पूर्ति का एक छोटा सा अनुपात होती है। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक प्रभावशाली रूप से साख नियंत्रण करने में असमर्थ होता है।